शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 47 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक-17 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 18-25 अप्रैल 2022 मूल्य पांच रूपए

अवरोधों के बावजूद मंडी के बाद कांगड़ा के शाहपुर में आप की दूसरी रैली भी रही सफल

- शांता और मनकोटिया के सवाल भी नहीं रोक पाये जनता को
- जेपी नड्डा की जनसभा भी केजरीवाल के प्रभाव को कम नहीं कर पायी
- प्रदेश में आप की विधिवत ईकाई न होने के बाद भी इतने लोगों का केजरीवाल को सुनने आने का अर्थ
- क्या जनता का जनसभा में आना बदलाव की मांग नहीं है?

शिमला/शैल। पंजाब में अप्रत्याशित जीत के बाद जैसे ही केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तभी से प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के समीकरण बदलने और बिगड़ने शुरू हो गये हैं। क्योंकि दोनों ही पार्टियों के नेता कार्यकर्ता आप में जाने शुरू हो गये हैं। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के मण्डी रोड शो से पहले भिंडरावाला के फोटो और खालिस्तान के झण्डे पंजाब से गये कुछ पर्यटकों के वाहनों पर लगे होने का मुद्दा उठा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की व्यक्तिगत प्रतिक्रिया इस पर आयी। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता शान्ता कुमार ने शानन विद्युत परियोजना का मुद्दा उठाने के लिये जयराम ठाकुर को पत्र लिखा। इन मुद्दों के सामने आने पर लगा कि केजरीवाल का मण्डी का प्रस्तावित रोड शो इससे प्रभावित होगा। लेकिन मण्डी के सफल रोड शो ने यह प्रमाणित कर दिया कि यह सारे प्रयास ''खिसयानी बिल्ली खम्बा नोचे'' से अधिक कुछ नहीं थे।

मंण्डी की रैली के बाद केजरीवाल का मुकाबला करने के लिये हिमाचल के सपूत राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मोर्चा संभाला। शिमला में रोड शो और पीटरहॉफ में रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन की पूर्व संध्या पर हमीरपुर के सांसद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भी फील्ड में उतारा गया और आधी रात को आप के तीन बड़े नेताओं को

भाजपा में शामिल करवा दिया गया। नड्डा के आवास पर यह सब कुछ घटा। लेकिन अगले ही दिन नड्डा की जनसभा में कुर्सियां खाली मिली। इसी बीच केजरीवाल की शाहपुर रैली घोषित हो गयी। इस रैली को असफल बनाने के लिये फिर केजरीवाल की सभा से एक दिन पहले 22 अप्रैल को नगरोटा -बगवां में जगत प्रकाश नड्डा का रोड शो और जनसभा रख दी गयी। यही केजरीवाल पर सवालों के तीर छोड़ने के लिये पूर्व मंत्री विजय सिंह मनकोटिया भी फील्ड में आ गये। वाकायदा एक पत्रकार वार्ता में तीखे सवालों के मिजाईल छोड़े गये। एक कांगड़ा गिद्धा प्रायोजित किया गया। इसमें भी केजरीवाल पर सवालों के नश्तर चुभाये गये। सोशल मीडिया मंचों पर यह गिद्धा खूब वायरल हुआ। लेकिन इतने सारे परोक्ष/अपरोक्ष प्रयासों के बावजूद केजरीवाल की सभा बहुत सफल रही। यह सफलता उस समय मिली है जब आप का कोई संगठन विधिवत घोषित नहीं है। केजरीवाल की दिल्ली की परफारमैन्स और पंजाब की उसी तरह की सफलता से ही आप आज हिमाचल में चर्चा का केंद्र बन गयी है।

प्रदेश सरकार और भाजपा द्वारा परोक्ष/अपरोक्ष में आप को रोकने के जितने भी प्रयास किये गये हैं उनसे प्रमाणित हो जाता है कि आप का मनोवैज्ञानिक दबाव सरकार पर लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा की गयी मुफ्ती की घोषणाएं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी मनोवैज्ञानिक दबाव को बढ़ाते हुये केजरीवाल ने भरी जनसभा में मुख्यमंत्री पर उनकी नकल करने का तंज कसा है। यह तंज कितना निशाने पर बैठा है इसका अनुमान मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया से लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने जब यह जवाब दिया कि प्रदेश की जनता लुटेरी नहीं है बल्कि मेहनती है। तब मुख्यमंत्री यह भूल गये कि केजरीवाल ने प्रदेश में रही सरकारों पर प्रदेश को लूटने का आरोप लगाया है। केजरीवाल का यह आरोप प्रदेश पर बढ़ते कर्ज के आंकड़ों और कैग रिपोर्टो में सरकार पर आयी टिप्पणियों से भी लगाया जा सकता है। लेकिन आप की ओर से अभी प्रदेश से जुड़े सवाल उठाये ही नहीं गये हैं। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि आप की प्रदेश इकाई में ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक सामने ही नहीं आया है जो प्रदेश से जुड़े तीखे सवाल भाजपा और कांग्रेस से पूछने शुरू करेगा। क्योंकि सवाल तो भाजपा और कांग्रेस से ही पूछे जायेंगे जो प्रदेश की सत्ता पर बारी-बारी से काबिज रहे हैं। अभी जिन सवालों को शान्ता कुमार और मनकोटिया ने उछाला है उन पर इनसे भी जवाब पूछा जाना बनता है क्योंकि यह लोग भी सत्ता में भागीदार रहे हैं। आज प्रदेश को लेकर पूछे जाने वाला हर सवाल हर उस नेता से भी पूछा जायेगा जो कभी प्रदेश की सत्ता से जुड़ा रहा है।

ऐसे में यह एक महत्वपूर्ण संकेत हो जाता है कि केजरीवाल की सभाओं में उस समय लोग आ रहे हैं जब प्रदेश में विधिवत रूप से आप की इकाई का तक गठित नहीं है। इस स्थिति में भी लोगों का केजरीवाल को इतनी संख्या में सुनने आना यह दर्शाता है कि लोग सही में अब भाजपा और कांग्रेस का विकल्प चाहते हैं। यह आने वाला समय बतायेगा कि आप लोगों की इस अपेक्षा को पूरा कर पाता पाता है या नहीं।

राज्यपाल ने हिमाचल पुलिस के ऑरकेस्ट्रा को प्रेरणा स्त्रोत पुरस्कार से सम्मानित किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश पुलिस के ऑरकेस्ट्रा हार्मनी ऑफ दि पाईन्स को प्रेरणा स्त्रोत पुरस्कार से सम्मानित किया। इस ऑरकेस्ट्रा ने मुम्बई में कलर टीवी के रियल्टी शो 'हुनरबाज' में न केवल प्रदेश पुलिस का प्रतिनिधित्व किया बल्कि अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश में राज्य का नाम भी रोशन किया है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हार्मनी ऑफ दि पाईन्स के माध्यम से समाज में उपयोगी संदेश प्रसारित किए जाने चाहिए। पूर्व में भी प्रदेश पुलिस बल नशा निवारण, कोरोना महामारी, यातायात प्रबन्धन इत्यादि पर वीडियो संदेश तैयार कर चुकी है तथा भविष्य में भी इसी तरह के सामाजिक सरोकारों पर इनका योगदान लिया जा सकता है।

राज्यपाल ने कहा कि खाकी वर्दी से सुसज्जित यह जवान इतने बेहतरीन और प्रतिभावान कलाकार हैं जिसकी जितनी प्रशंसा की जाये कम है।

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि उन्होंने इस बैण्ड के प्रदर्शन के वीडियो देखे हैं और इसके सम्बन्ध में गोवा से भी उन्हें प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। इनके हुनर का कोई मुकाबला नहीं और हमें इन पर गर्व है।

राज्यपाल ने कहा कि बैण्ड की इस उपलब्धि के उपरान्त पुलिस के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आया है और यह जनमित्र पुलिस की छवि को और सुदृढ़ करेगा। उन्होंने इस बैण्ड के सार्वजनिक प्रदर्शन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बैण्ड को रिकॉर्डिंग के लिए एक समर्पित स्टूडियो स्थापित किए जाने से इनके प्रस्तुतिकरण में और निखार आयेगा। उन्होंने प्रदेश पुलिस की अब तक की यात्रा और उल्लेखनीय कार्यो से सम्बन्धित एक म्यूजिकल वीडियो तैयार करने का भी आग्रह किया। उन्होंने इस बैण्ड की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पुलिस महानिदेशक संजय कुण्डू के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके योगदान से यह बैण्ड आज देशभर में चर्चा का विषय बना है और बैण्ड के प्रत्येक कलाकार को उचित मान-सम्मान प्राप्त हो रहा है।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक संजय कुण्डू ने राज्यपाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑरकेस्ट्रा जिसे हार्मनी ऑफ दि पाईन्स के नाम से जाना जाता है की स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी। उन्होंने कहा कि इस ऑरकेस्ट्रा ने अपनी यात्रा छोटे स्तर से शुरू की जिसमें प्रदेश पुलिस के प्रतिभावान जवान पुलिस विभाग तथा रेडक्रॉस सोसायटी के विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति देते थे। इसके उपरान्त पुलिस अ रकेस्ट्रा ने भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, दूरदर्शन सहित विभिन्न राज्य स्तरीय विभिन्न मेलों इत्यादि में भी अपनी प्रस्तुति देना प्रारम्भ किया।

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि विभागीय स्तर पर ऑरकेस्ट्रा को निरन्तर प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान किया जा रहा है ताकि वे अपने कौशल में और निखार ला सकें। इस ऑरकेस्ट्रा को हाल ही में अत्याधुनिक संगीत वाद्य यन्त्र और अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई है और इनके गीतों इत्यादि को रिकॉर्ड करने के लिए एक समर्पित स्टूडियो उपलब्ध करवाने के भी प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में बाल एवं महिला अपराधों की रोकथाम, सड़क दुर्घटनाओं, संगठित अपराधों इत्यादि के प्रति जागरूकता से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर वीडियो तैयार करने की भी योजना है।

इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑरकेस्ट्रा द्वारा 'हुनरबाज देश की शान' और अन्य गीतों पर अपनी प्रस्तुति दी गई। ऑरकेस्ट्रा ने अन्य लोकप्रिय गीतों की लड़ी भी प्रस्तुत की।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सी.आई.डी. एन. वेणुगोपाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अभिषेक त्रिवेदी, पूर्व पुलिस महानिदेशक आर.आर.वर्मा और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने शिमला आर्ट फेस्ट का दौरा किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि हर कला में एक सन्देश अन्तर्निहित होता है। इस सन्देश को समझने और समाज में इसके बारे में जगरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।

भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा शिमला के रिज मैदान पर आयोजित शिमला आर्ट फेस्ट में राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुये। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों से कोविड महामारी के कारण इस फेस्ट का आयोजन नहीं किया जा सका था। उन्होंने कहा कि देश के चित्रकारों और राज्य के कलाकारों के लिए यह एक अच्छा अवसर है, जिसके माध्यम से उन्हें एक उचित मंच प्रदान किया गया है, जिसके लिए विभाग सराहना का पात्र है।

पद्मश्री श्याम शर्मा ने राज्यपाल को अपनी कलाकृतियों से अवगत कराया। 22 से 24 अप्रैल तक आयोजित इस उत्सव में 200 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया। इस बार 25 कलाकारों को आमंत्रित किया गया था। सभी प्रतिभागी कलाकारों को विभाग द्वारा कैनवास और रंग प्रदान किए गए। इस फेस्ट का आयोजन वर्ष 2017 से किया जा रहा है।

इस अवसर पर भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के निदेशक डॉ. पंकज ललित ने राज्यपाल का स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को राजभवन में जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने राज्यपाल की दीर्घायु व स्वस्थ जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी साधना ठाकुर इस अवसर पर उनके साथ उपस्थित थीं। लेडी गवर्नर अनघा आर्लेकर भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केन्द्र व प्रदेश मंत्रिमण्डल के सदस्यों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी राज्यपाल को दूरभाष पर जन्मदिन की बधाई दी।

इससे पहले राज्यपाल ने प्रात: राजभवन की यज्ञशाला में परिजनों के साथ यज्ञ में भाग लिया तथा राजभवन परिसर में पोपुलर का पौधा रोपित किया। उन्होंने राजभवन के कर्मचारियों के साथ दीप प्रज्ज्वलित कर अपना जन्मदिन मनाया।

पुलिस महा निदेशक संजय कुंडू, प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन अजय श्रीवास्तव, शिमला और नौणी विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के धरोहर पर्यटन कॉन्क्लेव का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (पीएचडीसीसीआई) द्वारा धरोहर-सतत विकास का प्रमुख माध्यम, विषय पर आयोजित 11वें अन्तरराष्ट्रीय धरोहर पर्यटन कॉन्क्लेव का शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस धरोहर कॉन्क्लेव के आयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश उपयुक्त स्थान है। उन्होंने स्वयं राज्य के कुछ दर्शनीय एवं मनोरम स्थलों की यात्रा की है और यहां के हर धरोहर स्थल में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि धरोहर सिर्फ भवनों में ही नहीं अपितु नदियां, झीलें, वन, मन्दिर और संस्कृति भी हमारी धरोहर हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाना चाहिए। इससे राज्य में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बर्ड वॉचर, फोटोग्राफर और अन्य लोग आकर्षित होंगे। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सतत आधारभूत संरचना का विकास अत्यन्त आवश्यक है ताकि पर्यावरण मित्र गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सके।

पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष प्रदीप मुल्तानी ने कहा कि भारत में पर्यटन क्षेत्र, विशेष रूप से धरोहर पर्यटन को मजबूत करने के लिए पीएचडीसीसीआई प्रतिबद्ध है। धरोहर पर्यटन कॉन्क्लेव की परिकल्पना वर्ष 2011 में की गई थी। उन्होंने कॉन्क्लेव के आयोजन के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

इस अवसर पर पीएचडीसीसीआई तथा इसके नॉलेज पार्टनर - ओआरजी इंडिया ने संयुक्त रूप से हेरिटेज एज अ की ड्राईवर ऑफ सस्टेनेबिलिटी नामक नॉलेज रिपोर्ट भी जारी की। इस रिपोर्ट में विश्व तथा देश में हेरिटेज पर्यटन का समग्र दृष्टिकोण दिया गया है।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

सुदर्शन अवस्थी

राज्यपाल ने युवा पीढ़ी से स्वामी विवेकानन्द की शिक्षाओं का अनुसरण करने का आग्रह किया

शिमला/शैल। भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के तत्वावधान में राधिका क्रिएशंस द्वारा शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित नाटक का मंचन किया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानन्द ने भारतीय दर्शन, वेदांत और योग पद्धति को पश्चिमी देशों में प्रचलित करने में अहम भूमिका निभाई और उन्हें 19वीं सदी के अंत में अध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाने और हिंदू धर्म को विश्व के प्रमुख धर्म के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है। उन्होंने कहा कि वे भारत में समकालीन हिंदू सुधार आन्दोलनों के प्रमुख प्रणेता थे और उन्होंने औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा में योगदान दिया।

उन्होंने राधिका क्रिएशन्स के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नाटक की सराहना की और कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन हम सभी के लिए एक आदर्श है तथा नई पीढ़ी को उनकी शिक्षाओं पर चलने की आवश्यकता है।

शुभांगी भड़बडे रचित इस नाटक का निर्देशन सारिका पेंडसे ने किया।

लेडी गवर्नर अनघा आर्लेकर भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। इससे पूर्व, राज्यपाल ने राम-नाम श्रृंखला पर आधारित स्वर्गीय सनत कुमार चटर्जी की चित्रकला प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

राज्यपाल ने प्रदर्शनी में गहन रुचि दिखाई और कहा कि महान कलाकार स्वर्गीय सनत कुमार चटर्जी के चित्रों के संग्रह में भारत की संस्कृति और आध्यात्मिकता को दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि 30 चित्रों की यह श्रृंखला राम नाम भारतीय जनमानस के दैनिक जीवन में राम नाम की उपस्थिति का चित्रण है।

सनत कुमार चटर्जी के पुत्र हिम चटर्जी ने भी राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश में कला के क्षेत्र में उनके योगदान से अवगत करवाया।

इस अवसर पर भाषा, कला एवं संस्कृति सचिव राकेश कंवर, निदेशक भाषा, कला एवं संस्कृति पंकज ललित और अन्य गणमान्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत बद्दी-बरोटीबाला -नालागढ़ नोड को शामिल करने के लिए केन्द्र का आभार व्यक्त किया

आगामी जून माह तक तैयार होगी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत विकसित किए जाने वाले 11 औद्योगिक कॉरीडोर के 32 नोड में हिमाचल प्रदेश के बद्दी-बरोटीबाला -नालागढ़ नोड को शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बीबीएन नोड को विकसित करने से संबंधित गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास निगम सीमित (एनआईसीडीसी) के प्रयासों की भी सराहना की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उद्योगों को संभारतंत्र (लॉजिस्टिकस) उपलब्ध करवाने, भविष्य के औद्योगिक नगर और राज्य में औद्योगिक विकास को और प्रोत्साहन प्रदान करने में दूरगामी साबित होगी। इस परियोजना से रोजगार के अवसर सृजित होंगे और आर्थिक उन्नति के साथ-साथ सर्वांगीण सामाजिक एवं आर्थिक सुनिश्चित होगा।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को मूर्तरूप प्रदान करने के लिए केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष प्रभावी ढंग से मामला उठाया था और अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरीडोर से इसे जोड़ने से न केवल विनिर्माण क्षेत्र बल्कि कृषि क्षेत्र को भी होने वाले सीधे लाभ से उन्हें अवगत करवाया था।

इसी कड़ी में राज्य सरकार के एक प्रतिनिधिमण्डल ने निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति के नेतृत्व में नई दिल्ली में राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास निगम सीमित (एनआईसीडीसी) के कार्यालय में आयोजित हितधारकों एवं परामर्शदाता संघों की बैठक में भाग लिया, जिसमें एनआईसीडीसी के वरिष्ठ अधिकारी और एलएण्डटी, पीडब्ल्यूसी और निप्पॉन-कोई की ओर से परामर्शदाता भी शामिल थे। यह बैठक मुख्य तौर पर अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरीडोर के अन्तर्गत बद्दी-बरोटीबाला-नालागढ़ (बीबीएन) नोड के लिए परियोजना विकास गतिविधियों के संबंध में चुनिंदा परामर्शदाता संघों के साथ आयोजित की गई। इसी माह के प्रारम्भ में एलएण्डटी के नेतृत्व वाले संघ को बीबीएन नोड की मास्टर प्लानिंग और प्रारम्भिक इंजीनियरिंग संबंधी परामर्श के लिए चयनित किया गया है।

राज्य सरकार की ओर से निदेशक उद्योग ने बैठक में जानकारी दी कि बीबीएन क्षेत्र में औद्योगिक नोड के विकास के लिए 4000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि उपलब्ध है। इस भूमि का स्टेट ऑफ आर्ट एकीकृत औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने और बेहतर आवासीय एवं सामाजिक अधोसंरचना की स्थापना में उपयोग किया जा सकता है।

निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति ने यह भी अवगत करवाया कि एनआईसीडीसी द्वारा अनुबंधित पेशेवर 26 अप्रैल से अपना कार्य प्रारम्भ कर देंगे और जून माह तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी।

राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास निगम सीमित की समीक्षा बैठक में देश में भविष्य के औद्योगिक नगरों की स्थापना और विश्व स्तरीय विनिर्माण सुविधाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर कार्यक्रम (एनआईसीपी) अपनाने पर सहमति बनी। इस कार्यक्रम का वृहद उद्देश्य विभिन्न सेक्टर में अगली पीढ़ी की तकनीकों के उपयोग से विश्व स्तरीय विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना है ताकि विश्व के उत्कृष्ट विनिर्माण और निवेश केन्द्रों से मुकाबला किया जा सके।

यह परियोजना प्रदेश सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही है और इसमें राज्य सरकार अपने परियोजना भागांश के रूप में भूमि उपलब्ध करवाएगी और नोड के विकास के लिए शेष व्यय केन्द्र सरकार वहन करेगी, जोकि राज्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई भूमि की कीमत के बराबर होगा। नोड को विकसित करने के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार संयुक्त रूप से कार्य करेगी। इस परियोजना की अधिकतम लागत 3000 करोड़ रुपये होगी। इसके अतिरिक्त, वॉयबल गैप फंडिंग के अन्तर्गत राज्य को 10 वर्षो के लिए ब्याजमुक्त ऋण का भी प्रावधान है।

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सौर ऊर्जा के दोहन में सार्थक प्रयास:सुरेश भारद्वाज

शिमला/शैल। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन सौर ऊर्जा के दोहन को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मिशन के तहत शिमला शहर के 66 सरकारी भवनों में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से 1.85 करोड़ रुपये की बिजली की बचत की गई है।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन ने शिमला शहर का कायाकल्प किया है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना इस मिशन का मुख्य घटक है। पहले शहर में सरकारी भवनों को चिन्हित किया गया तथा उसके बाद प्रदेश में सौर ऊर्जा की नोडल एजेंसी हिमऊर्जा के माध्यम से इन भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया आरम्भ की गई।

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र जनवरी 2019 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया। अब तक 66 सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये गये हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 किलोवाट आवर है। अब तक इन संयंत्रों के माध्यम से 39.16 लाख किलोवाट आवर ऊर्जा का उत्पादन किया गया है, जिससे 1.85 करोड़ रुपये की बिजली की बचत हुई है। सरकारी प्रिंटिंग प्रेस, एचआरटीसी कार्यशाला तारादेवी, बागवानी निदेशालय, हि.प्र. विश्वविद्यालय में छात्रावास, एचआरटीसी का पुराना बस स्टैंड, डीडीयू जोनल अस्पताल, जिला न्यायालय चक्कर कुछ ऐसे कार्यालय हैं जिन्होंने अब तक प्रति कार्यालय बिजली बिलों पर 3 लाख रुपये से अधिक की बिजली की बचत की है और एक लाख यूनिट से अधिक का उत्पादन किया।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा हरित ऊर्जा विशेषकर सौर ऊर्जा पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि हम हरित ऊर्जा के साथ स्मार्ट सिटी के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा स्मार्ट सिटी का भविष्य है। ऐसी कई परियोजनाएं हैं, जहां मुख्य रूप से बिजली बिलों पर खर्च किया जायेगा। ऐसी सभी परियोजनाओं विशेष कर लिफ्ट और एस्केलेटर को जोड़ने के लिए सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने की योजना तैयार की गई है।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अधिकारियों को संजौली में निर्माणाधीन फुट ओवर ब्रिज में एस्केलेटर की संभावना तलाशने को कहा गया है। हिम ऊर्जा द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की संभावना भी तलाश की जायेगी, जिससे बिजली खर्च कम होगा और एस्केलेटर अधिक व्यावहारिक हो जायेगा।

जल शक्ति व स्वास्थ्य विभाग जलजनित रोगों की रोकथाम के लिए करेंगे साझा प्रयास:महेन्द्र सिंह ठाकुर

शिमला/शैल। जल शक्ति, राजस्व, बागवानी व सैनिक कल्याण मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व आयुर्वेद मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने जल जॉच किटयुक्त

जीवनधारा मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जल शक्ति विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ मिलकर जलजनित रोगों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही जीवनधारा योजना की मोबाइल मेडिकल यूनिट में जल जांच की सुविधा भी उपलब्ध करवायेगा। इस बारे में 15 मार्च, 2022 को जल शक्ति विभाग व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मध्य दोनों विभागों के दायित्व को सुनिश्चित करते हुये एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार पेयजल स्रोतों और वितरण प्रणाली से नमूनों की जॉच का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है ताकि जल गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए प्रदेश में प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ ढांचा तैयार किया जा रहा है। अभी तक 60 प्रयोगशालायें स्थापित की जा चुकी हैं, जिनमें से सात इसी वर्ष स्थापित की गई हैं। इन प्रयोगशालाओं में से 50 को उच्च मानकों के आधार पर राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता मिल चुकी है। इसी कड़ी में प्रदेश के दुर्गम, दूर-दराज और सुविधा के अभाव वाले क्षेत्रों में जल गुणवत्ता को और पुख्ता करने के लिए अब जल शक्ति विभाग व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने साझा प्रयास के लिए सहमति जताई है।

उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग आरम्भ में पांच अत्याधुनिक मोबाइल टैस्ट किट उपलब्ध करवा रहा है, जिनमें आधुनिक उपकरण भी शामिल हैं। इस पेयजल जॉच किट के माध्यम से सात जरूरी मापदण्डों का भौतिक, रसायनिक व जीवाणु परीक्षण किया जायेगा और एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसके परिणाम सांझा किये जायेंगे। जीवनधारा वैन में तैनात प्रयोगशाला तकनीशियन को पेयजल जॉच किट के संचालन का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा चुका है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व आयुर्वेद मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जीवनधारा मोबाइल वैन प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में कार्य कर रही हैं। उन्हीं क्षेत्रों में से पांच जिलों शिमला, सोलन, मण्डी, चम्बा व कांगड़ा जहां जलजनित रोगों की पूर्व में घटनायें हो चुकी हैं, उन स्थानों पर जल गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए जल शक्ति विभाग व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने यह साझा प्रयास शुरू किया है ताकि स्वास्थ्य जॉच के साथ-साथ इन क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता जॉच कर जलजनित रोगों की रोकथाम के लिए कार्य किया जा सके।

इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक हेमराज बैरवा, जल शक्ति विभाग के प्रमुख अभियन्ता, ई. संजीव कौर तथा मुख्य अभियन्ता ई. जोगिन्द्र सिंह चौहान सहित दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

वर्ष 2021-22 में राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने 8403.70 करोड़ रुपये राजस्व एकत्र किया

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोविड-19 महामारी की दूसरी और तीसरी लहर के बावजूद विभाग द्वारा सभी शीर्षो के अन्तर्गत कुल 8403.70 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया गया है, जोकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में सभी शीर्षो में एकत्र कुल राजस्व 7044.24 करोड़ रुपये से 19.30 प्रतिशत अधिक है।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व में अधिक बढ़ोतरी के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा सरकार के दिशा-निर्देशों की समयबद्ध पालना व उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए अथक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों में बढ़ोतरी के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर विभागीय समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया। सरकार द्वारा विभागीय अधिकारियों को लैपटॉप और टैबलेट दिए गए, जिससे उन्हें ई-वे बिल सत्यापन, आईटीसी असन्तुलन, जीएसटी की वापसी (रिफंड) व अन्य जीएसटी से संबंधित ऑनलाइन कार्यो का समय पर निपटान करने में सहायता मिली।

प्रधान सचिव, राज्य कर एवं आबकारी सुभासीष पन्डा ने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी राजस्व प्राप्तियों में बढ़ोतरी के लिए बेहतर प्रयत्न करने को प्रोत्साहित किया।

अम्ब में छात्रा की हत्या के मामले में एक सप्ताह के भीतर चालान फाइल करने के निर्देश

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि जिला ऊना के अम्ब में हुई 15 वर्षीय छात्रा की निर्मम हत्या की छानबीन के लिए गठित की गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने इस प्रकरण की जांच पूरी कर ली है। पुलिस विभाग ने इस बारे में अवगत करवाया है और अब केवल फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट आनी शेष है जो 3-4 दिनों के भीतर प्राप्त हो जायेगी। इसके उपरान्त दो दिनों के भीतर न्यायालय में चालान पेश कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस संवेदनशील मामले की मुख्यमंत्री ने 18 अप्रैल, 2022 को समीक्षा के उपरांत गृह व पुलिस विभाग को एक सप्ताह के भीतर चार्जशीट/चालान फाइल करने के निर्देश दिए थे। यह भी निर्देश दिए कि इस मामले की शीघ्र दैनिक आधार (फास्ट ट्रैक) पर सुनवाई के लिए न्यायालय में याचिका दायर की जाए, ताकि दोषी को इस अमानवीय अपराध के लिए कानून के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र उचित सजा दिलाई जा सके।

मनुष्य जितना अपने अंदर से करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा, वह संसार को भी उसी तरह पायेगा।
.....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

कांग्रेस का प्रशांत प्रयोग

पांच राज्यों में मिली चुनावी हार ने कांग्रेस को पेशेवर चुनावी रणनीतिकार की सेवायें लेने के मुकाम पर पहुंचा दिया है। अब साथ ही यह सवाल भी उठने लग पड़ा है कि यदि प्रशांत प्रयोग भी सत्ता में वापसी न करवा पाया तो कांग्रेस कहां जायेगी? कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी है जिसका देश के निर्माण में एक निश्चित योगदान रहा है। आजादी के वक्त सैकड़ों रियासतों में बंटे देश में केंद्रीय लोकतांत्रिक सत्ता की स्थापना कर पाना कोई आसान काम नहीं था। क्योंकि आज जिस तरह से सार्वजनिक संसाधनों को विनिवेश के नाम पर प्राइवेट सैक्टर को सौंपा जा रहा है यदि यही सब कुछ पहले आम चुनाव के साथ ही कर दिया जाता तो शायद यह देश कुछ अमीर लोगों की व्यक्तिगत संपत्ति बनकर ही रह जाता। उस समय की सरकार के सामने कृषि बैंकिंग और राजाओं के प्रिवीपर्सो की नीतियों में बदलाव करना प्राथमिकता थी। इस दायित्व को उन्होंने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। लेकिन उस समय भी इन बदलावों का विरोध हुआ और उसमें सी.राज गोपालाचार्य, चौधरी चरण सिंह, मीनू मसानी, के.एफ.रुस्तम जी और प्रो.बलराज मधोक जैसे नाम प्रमुखता से सामने आते हैं। यह जिक्र इसलिये आवश्यक हो जाता है क्योंकि आज निजीकरण सबसे बड़ा आर्थिक सवाल बन चुका है।

इस परिदृश्य में यदि आकलन किया जाये तो कांग्रेस के सारी वस्तुस्थिति को मुख्य रूप से नेहरू तक का कार्यकाल, उसके बाद 1977 तक और फिर 1977 से आज तक यह एक व्यवहारिक सच है कि कांग्रेस नेतृत्व नेहरू परिवार की परिधि से आज तक बाहर नहीं निकल पाया है। इसका कारण यह रहा है कि देश के सबसे धनी परिवार ने देश की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिये अपना सब कुछ राष्ट्र को दे दिया और यह देना ही परिवार को कांग्रेस का केंद्र बना गया। जबकि नेहरू के कार्यकाल में भी संगठन में कामराज प्लान जैसी योजनायें आयी। इंदिरा गांधी को पार्टी में स्थापित होने के लिये कांग्रेस में दो बार विघटन की स्थितियों का सामना करना पड़ा। जिस तरह से इंदिरा गांधी को स्थापित होने के लिए संघर्ष करना पड़ा वही स्थिति राजीव गांधी के लिए भी बनी थी और आज सोनिया, राहुल और प्रियंका के लिये भी वैसी ही स्थितियां निर्मित होती जा रही है। क्योंकि आर्थिक सोच को लेकर ही टकराव देश की राजनीति का एक स्थायी चरित्र बन चुका है। आज इस आर्थिक अवधारणा के टकराव को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आवरण से ढकने का प्रयास किया जा रहा है। तेतीस करोड़ देवी देवताओं की अवधारणा वाले देश को धर्म के गिर्द केंद्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस व्यवहारिक वस्तुस्थिति को यदि और गंभीरता से समझा जाये तो यही सामने आता है कि हर बार सत्ता परिवर्तन नेहरू काल से लेकर आज मोदी काल तक भ्रष्टाचार के नाम पर ही होता रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार के एक भी बड़े आरोप को प्रमाणित नहीं किया जा सका है। 2014 में भी इसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता परिवर्तन हुआ लेकिन आज तक इसका कोई परिणाम सामने नहीं आया है। जबकि आज इसका आकार और प्रकार दोनों ही कई गुना बढ़ चुके हैं। इस बढ़ौतरी को कोई भी मुद्दा नहीं बना पा रहा है। जबकि महंगाई और बेरोजगारी दोनों इसी के परिणाम हैं। सत्ता में बने रहने के लिये चुनाव लगातार महंगे होते जा रहे हैं। हर छोटे-बड़े चुनाव से पहले धार्मिक और जातीय हिंसा एक बड़ा हथियार बनती जा रही है। हर चुनाव में ईवीएम पर गंभीर से गंभीर सवाल उठते जा रहे हैं। आम आदमी ईवीएम को संदेश से देख रहा है। लेकिन राजनीतिक दल अभी तक इस पर स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ दल से सत्ता छीनने में जनता के सवालों लेकर जनता में जाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को लेकर अपने ही संगठन से शुरुआत करनी पडेगी।

इस परिदृश्य में यह सवाल रोचक होगा कि प्रशांत किशोर भाजपा के प्रचार तंत्र का मुकाबला करने के लिये किस तरह की नीति पर चलने का सुझाव देते हैं। वह अपने ही सूत्रों के दम पर क्या कांग्रेस का उम्मीदवार बन कर चुनाव लड़ने का साहस दिखायेंगे? क्या पी के सही में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? क्या वह एक राजनीतिक चिंतक होने के नाते कांग्रेस को सहयोग कर रहे हैं? आज सरकार की आर्थिक नीतियां सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई हैं। ऐसे में किसी भी दल को सहयोग देने से पहले यह स्पष्ट करना होगा कि उनकी अपनी आर्थिक सोच क्या है? अन्यथा किसी भी पेशेवर की सलाह पर अमल करना सार्थक परिणाम ही देगा यह तय नहीं माना जा सकता।

मूर्खता व जाहिलपन का इस्लाम में कोई स्थान नहीं

गौतम चौधरी

इस्लाम के सबसे अंतिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सबसे पहले पवित्र कुरान की पांच आयतें नाज़िल हुई थी। उसका हिन्दी तर्जुमा है, ''पढ़ अपने उस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। उसने पैदा किया इंसान को खून के लोथरे से। पढ़ और तेरा रब बड़ा करीम यानी दयालू है। जिसने इंसान को कलम के पढ़ना सिखाया और सिखाया उन चीजों को जिसके बारे में इंसान नहीं जानता था।'' ये पांच आयतें कुरान मजीत सूरे एकरा का अंग है।

यह पहला सूरा था जो पैगंबर मुहम्मद के सामने प्रकट हुआ था और आज की दुनिया में मुसलमानों के लिए इसका सबसे अधिक महत्व है। टिप्पणीकारों के अनुसार, यह सूरा इस्लाम में शिक्षा की केंद्रीयता और महत्व को दर्शाता है। यह इमान वालों को पढ़ने का आदेश देता है। शब्द 'इकरा' एक आदेश है जिसका अरबी में अर्थ है पढ़ना और यह सीखने, नए की खोज करने और ज्ञान प्राप्त करने की धारणाओं का सुझाव देता है।

इस्लाम ने अपने अनुयायियों के लिए शिक्षा को बहुत महत्व दिया है और इसकी एक लंबी और शानदार बौद्धिक विरासत है। इस्लाम में ज्ञान (इल्म) को अत्यधिक महत्व दिया जाता रहा है, जैसा कि इस्लाम के सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान में इसके 800 से अधिक संदर्भो से संकेत मिलता है।

कुरान में शिक्षा के महत्व को कई दायित्वों के साथ उजागर किया गया है, जैसे-''ऐ रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कह दो, क्या जो लोग जानते हैं, क्या वे उनके बराबर हैं जो नहीं जानते? कोई भी इस बारे में ध्यान नहीं देगा, सिवाय तर्क के लोगों के (कुरान, 39:9)। इस्लाम में शिक्षा के महत्व को इस तथ्य से पता लगाया जा सकता है कि बद्र की लड़ाई के बाद, पैगंबर मुहम्मद ने युद्धबंदियों में से शिक्षित कैदियों को बिना किसी शुल्क के रिहा करने का संकल्प लिया, बशर्ते वे अपने ही साथियों के बीच अनपढ़ और अज्ञानी को पढ़ना और लिखना सिखा सकें। इसे गैर-इस्लामी लोगों तक विस्तारित किया गया, जिससे उन्हें सीखने का अधिकार मिला और यहां तक कि सीखने के लिये विरोधियों की सेवाओं की मांग को उपयोग करने की अनुमति दी गई।

कुरान की प्रधानता और इस्लामी परंपरा में इसके अध्ययन के कारण, शिक्षा ने अपनी स्थापना से ही इस्लाम में एक प्रमुख भूमिका निभाई। समकालीन काल से पहले, शिक्षा अरबी और कुरान के अध्ययन के साथ शुरू हुई थी। इस्लाम की पहली कुछ शताब्दियों के लिए, शैक्षिक सेटिंग्स काफी हद तक अनौपचारिक थीं, लेकिन 11वीं और 12वीं शताब्दी से शुरू होकर, शासक अभिजात वर्ग ने उच्च धार्मिक अध्ययन के स्थानों का निर्माण करना शुरू कर दिया।

जब पश्चिमी यूरोप वैज्ञानिक रूप से आदिम और स्थिर था, इस्लामी शिक्षा दसवीं और तेरहवीं शताब्दी के बीच तर्कसंगत विज्ञान, कला, और अद्भुत ग्रहणशीलता के साथ फली-फूली। यह एक ऐसा दौर था जिसमें असहमति का सम्मान किया जाता था और रचनात्मक आलोचनाओं को स्वीकार कर ली जाती थी। इस अवधि के दौरान इस्लामी दुनिया ने विज्ञान, वास्तुकला और साहित्य में मानव सभ्यता को सबसे अधिक योगदान दिया। हैरानी की बात यह है कि इस्लामी शिक्षाविदों ने ग्रीक छात्रवृत्ति को संरक्षित रखा, जिसे ईसाई दुनिया ने मना किया था।

रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गणित जैसे क्षेत्रों में अन्य उल्लेखनीय विकास हुये, इस बीच कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने वैज्ञानिक प्रमाणों को वस्तुनिष्ठ वास्तविकता और धार्मिक सत्य के सही प्रवेश के साधन के रूप में देखा।

ज्ञान प्राप्त करना हर मुस्लिम पुरुष या महिला पर एक दायित्व है। ज्ञान प्राप्त करना हर मुसलमान का कर्तव्य है (इब्न माजा)। शिक्षा की आवश्यकता और महत्व के बारे में कुरान और हदीस में कई अन्य संदर्भ हैं। ऐसा नहीं है कि समकालीन मुसलमान इन आज्ञाओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं, बल्कि गरीबी और राजनीति के परिणामस्वरूप भारतीय मुसलमानों में उच्च स्तर की निरक्षरता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस्लाम धार्मिक ज्ञान और सांसारिक ज्ञान के बीच अंतर नहीं करता है, जैसा- कई मुस्लिम धार्मिक उलेमाओं द्वारा कहा जाता है। बल्कि, कुरान की आयतें हमें जीवन की उत्पत्ति, अंतरिक्ष, सौर मंडल एवं खगोलीय पिंडों के बारे में बताती हैं। यह हमें जीवन के चक्रों और विभिन्न प्रजातियों के रहने या ग्रह पृथ्वी पर रहने वाली प्रजातियों के बारे में भी बताती है। इसलिए जीवन की प्रक्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान जीवन को आसान बनाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे पृथ्वी पर समृद्धि लाने के लिये साथी व्यक्तियों और अन्य प्राणियों के साथ सद्भावपूर्वक रहना है। पवित्र कुरान की शिक्षा का यह एक महत्वपूर्ण संदेश है।

(पवित्र कुरान के संदर्भो की व्याख्या इस्लामिक विद्वान रांची पथलखुदवा मस्जिद के इमाम मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर कासमी के द्वारा की गयी है।)

प्रदेश सरकार द्वारा सड़क संरचना विकास पर बल के प्रभावी परिणाम

शिमला। अधोसंरचना विकास राज्य में विकास की गति प्रदान करने में अहम भूमिका निभाता है और सड़क अधोसंरचना को विकसित करने से विकास पर कई गुणा प्रभाव पड़ता है। रेल व हवाई यातायात के सीमित साधनों के कारण हिमाचल में सड़कों का महत्व और भी बड़ जाता है, इसलिए राज्य सरकार हिमाचल में सड़क सम्पर्क को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दे रही है।

हिमाचल प्रदेश में कुल 40,020 किलोमीटर लम्बी सड़कें हैं व राज्य सरकार द्वारा 10591 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है तथा 2278 पुल निर्मित किए गए हैं। राज्य सरकार ने केवल चार वर्षो की अवधि में हिमाचल प्रदेश में 3527 किलोमीटर वाहन योग्य सड़कें, 268 किलोमीटर जीप योग्य सड़कें और 268 पुलों का निर्माण किया हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया है और नवनिर्मित पंचायतों में सड़क सम्पर्क प्रदान करने के उद्देश्य से हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायतों के पुनर्गठन से ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 3615 हो गई है, इनमें से 3556 पंचायतें सड़क से जुड़ी हैं व शेष 59 पंचायतों में से 20 पंचायतों को 2022-23 में सड़क से जोड़ा जाएगा। वर्ष 2019 से दिसम्बर, 2021 तक 219 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया जिनकी आबादी 1500 से अधिक है, 1000 से 1499 की आबादी वाले 296 गांवों, 500 से 999 की आबादी वाले 1324 गांवों, 250 से 499 की आबादी वाले 3655 गांवों तथा 250 से कम आबादी वाले 5097 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है।

वर्तमान में 19 राष्ट्रीय उच्च मार्ग, जिनकी कुल लम्बाई 2592 किलोमीटर है, राज्य सड़क नेटवर्क की मुख्य जीवन रेखा है, जिनमें से 1238 किलोमीटर सड़कों का रख-रखाव और विकास हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 865 कार्य पूर्ण किए जा चुके है और 5408 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य किया गया है।

राज्य में ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि-नाबार्ड के तहत 68 पुल तथा 498 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि के तहत राज्य में 28 पुल निर्मित किए गए हैं तथा 65.8 किलोमीटर लम्बी सड़कों का उन्नयन किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया गया है। वर्ष 2020 में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मण्डी जिले को 30 जिलों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया जबकि हिमाचल प्रदेश ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। जिला मण्डी ने 2020-21 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सबसे अधिक लम्बाई के सड़क निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया।

राज्य के अन्य सात जिलों जैसे सोलन, चम्बा, शिमला, कांगड़ा, ऊना, सिरमौर और हमीरपुर ने भी देश के सर्वश्रेष्ठ 30 जिलों में अपना स्थान बनाया। हिमाचल प्रदेश में पीएमजीएसवाई कार्यक्रम के तहत 23 अक्तूबर, 2020 तक 1104 किलोमीटर सड़क निर्माण कर बेहतरीन प्रदर्शन किया है।

केन्द्र सरकार ने आम जनता के हितों की रक्षा के लिए निधि नियम, 2014 में संशोधन किया

नियमों में प्रावधान किया गया है कि निधियों के रूप में कार्य करने की इच्छुक सार्वजनिक कंपनियों को जमा स्वीकार करने से पहले केन्द्र सरकार से पूर्व घोषणा प्राप्त करनी होगी

शिमला। कम्पनी कानून, 1956 के तहत, एक निधि या म्यूचुअल बेनेफिट सोसाइटी का अर्थ एक ऐसी कम्पनी है जिसे केन्द्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा आधिकारिक राजपत्र में निधि या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी के रूप में घोषित किया है। कम्पनी कानून, 2013 के तहत, शुरू में किसी कम्पनी को निधि कम्पनी के रूप में कार्य करने के लिए केन्द्र सरकार से घोषणा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसी कम्पनियों को केवल निधि के रूप में शामिल करना आवश्यक होता था और निधि नियमावली के नियम 5 के उप–नियम (1) के तहत आवश्यकताएं पूरी करनी होती थीं, जैसे कि 200 की न्यूनतम सदस्यता, 10 लाख रुपये की शुद्ध स्वामित्व वाली निधि (एनओएफ), एनओएफ को 1:20 के अनुपात में जमा करना होता था और निधि नियम, 2014 के प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर 10 प्रतिशत भार मुक्त जमा राशि नियत वाणिज्यिक बैंकों या डाकघरों में जमा करनी होती थी।

कम्पनी कानून, 2013 के कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए मंत्रालय में एक समिति गठित की गई थी और अन्य बातों के साथ, यह महसूस किया गया कि निधि के रूप में घोषणा के लिए केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिए आवश्यक कम्पनी कानून, 1956 के तहत पूर्व में किए गए प्रावधान उपयुक्त हैं क्योंकि वे ऐसी संस्थाओं के नियमन के लिए एक केन्द्रीकृत और अधिक प्रतिबंधत्मक ढांचा प्रदान करते हैं और तदनुसार कम्पनी कानून, 2013 की धारा 406 में 15.08.2019 से संशोधन किया गया, ताकि केन्द्र सरकार द्वारा निधि के रूप में घोषणा की आवश्यकता को वापस लाया जा सके।

कम्पनी कानून, 2013 में 15.08.2019 के संशोधन और निधि नियमों, 2014 में परिणामस्वरूप 15.08.2019 से हुए संशोधन के बाद निधियों के रूप में शामिल की गई कम्पनियों के लिए यह अनिवार्य था कि वे शामिल होने के 14 महीनों के भीतर घोषणा के लिए फॉर्म एनडीएच–4 में केन्द्र सरकार को आवेदन करें, यदि उन्हें निधि (संशोधन) नियमों के 15.08.2019 से प्रभावी होने के बाद और निधि (संशोधन) नियमों के लागू होने के 09 महीने के भीतर, 2014 के बाद लेकिन 15.08.2019 से पहले निधि के रूप में शामिल किया जाता है।

कम्पनी कानून, 1956 के तहत लगभग 390 कम्पनियों को केवल निधि कम्पनी घोषित किया गया था। 2014–2019 के दौरान, दस हजार से अधिक कम्पनियों को शामिल किया गया। हालांकि, घोषणा के लिए केवल 2,300 कंपनियों ने एनडीएच–4 फॉर्म में आवेदन किया। फॉर्म एनडीएच–4 की जांच से पता चला है कि कम्पनियां कानून और निधि नियम, 2014 (संशोधित) के लागू प्रावधानों का पालन नहीं कर रही हैं। आम जनता के हितों की रक्षा के लिए, यह अनिवार्य हो गया है कि इसका सदस्य बनने से पहले, किसी को भी केन्द्र सरकार द्वारा एक कम्पनी को निधि के रूप में घोषित करना सुनिश्चित करना चाहिए और इसके लिए नियमों में कुछ आवश्यक/महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं जो निधि (संशोधन) नियम, 2022 के बाद शामिल की जाने वाली कम्पनियों पर निम्नानुसार लागू है–

10 लाख रुपये की शेयर पूंजी के साथ निधि के रूप में शामिल एक सार्वजनिक कंपनी को खुद को निधि के रूप में घोषित कराने के लिए शामिल होने के 120 दिनों के भीतर 20 लाख रुपये का एनओएफ के साथ सबसे पहले 200 की न्यूनतम सदस्यता के साथ फॉर्म एनडीएच–4 में आवेदन करना होगा।

कम्पनी के प्रमोटरों और निदेशकों को नियमों में निर्धारित फिट और उचित व्यक्ति के मानदंडों को पूरा करना होगा।

समय पर निपटान के लिए, संशोधित नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि केन्द्र सरकार एनडीएच–4 के रूप में कम्पनियों द्वारा दायर आवेदनों की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं लेती है, तो मंजूरी को स्वीकृत माना जाएगा। यह ऐसी कम्पनियों के लिए लागू होगा जिन्हें निधि (संशोधन) कानून, 2022 के बाद शामिल किया जाएगा।

अटल पेंशन योजना के तहत कुल नामांकन ने 4 करोड़ के आंकड़े को पार किया

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अटल पेंशन योजना के तहत 99 लाख से अधिक खातों का नामांकन किया गया

शिमला। मार्च 2022 तक अटल पेंशन योजना के तहत कुल नामांकन ने 4.01 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है, जिसमें से 99 लाख से अधिक अटल पेंशन योजना के खाते वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान खोले गए थे। सभी श्रेणी के बैंकों की सक्रिय भागीदारी के कारण इस योजना को यह जबरदस्त सफलता मिली। लगभग 71 प्रतिशत नामांकन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा, 19 प्रतिशत नामांकन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा, 6 प्रतिशत नामांकन निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा, 3 प्रतिशत नामांकन भुगतान एवं लघु वित्त बैंकों द्वारा किया गया।

भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक श्रेणी में वार्षिक लक्ष्य हासिल किया।

जबकि विदर्भ कोंकण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, उत्तरबंगा क्षेरिया ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, ओडिशा ग्राम्य बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुधारा ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, पुडूवई भरथियार ग्राम बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, मणिपुर रूरल बैंक और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक श्रेणी में वार्षिक लक्ष्य हासिल किए।

इसके अलावा, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, श्री महिला सेवा सहकारी बैंक, द कालूपुर कमर्शियल को–ऑपरेटिव बैंक, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को–ऑपरेटिव बैंक और राजकोट नागरिक सहकारी बैंक ने अन्य बैंक श्रेणियों में वार्षिक लक्ष्य हासिल किया।

बैंकों के अलावा बिहार, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और त्रिपुरा के 9 राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों ने अटल पेंशन योजना के तहत वार्षिक लक्ष्य हासिल किए।

31 मार्च, 2022 तक अटल पेंशन योजना के तहत कुल नामांकन में से, लगभग 80 प्रतिशत ग्राहकों ने 1000 रुपये की पेंशन योजना और 13 प्रतिशत ग्राहकों ने 5000 रुपये की पेंशन योजना का विकल्प चुना है। अटल पेंशन योजना के कुल ग्राहकों में से 44 प्रतिशत महिला ग्राहक हैं जबकि 56 प्रतिशत पुरुष ग्राहक हैं। इसके अलावा, अटल पेंशन योजना के कुल ग्राहकों में से, 45 प्रतिशत ग्राहकों की आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच है।

वर्ष 2021 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने प्रत्येक पात्र व्यक्ति को अटल पेंशन योजना का लाभ पहुंचाने सहित सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की संतृप्ति पर जोर दिया। सरकार के संतृप्ति मिशन के अनुरूप, पीएफआरडीए ने देश भर में सभी एसएलबीसी और आरआरबी के सहयोग से आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने का बीड़ा उठाया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, ऐसे 13 आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए और शेष कार्यक्रम चालू वित्तीय वर्ष में आयोजित किए जायेंगे।

पीएफआरडीए ने वेबिनार और टाउनहॉल की बैठकों के माध्यम से अटल पेंशन योजना के आउटरीच कार्यक्रमों के लिए अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और एनआरएलएम/एसआरएलएम जैसी एजेंसियों को शामिल करते हुए, जन धन खाताधारकों को लक्षित करने, युवाओं को लक्षित करने के लिए नामांकन के डिजिटल मोड को बढ़ावा देने की रणनीति बनाई है।

अटल पेंशन योजना पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित भारत सरकार की सुनिश्चित पेंशन योजना है। यह योजना भारत के 18–40 वर्ष के आयु वर्ग के किसी भी नागरिक को बैंक या डाकघर की शाखाओं, जहां उसका बचत बैंक खाता है, के माध्यम से शामिल होने की अनुमति देती है। इस योजना के तहत, एक ग्राहक को उसके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु से 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये प्रति माह तक का न्यूनतम गारंटी पेंशन मिलेगा। ग्राहक की मृत्यु के बाद उसके जीवनसाथी को समान पेंशन का भुगतान किया जाएगा और ग्राहक और उसके जीवनसाथी, दोनों, के निधन पर ग्राहक की 60 वर्ष की आयु तक जमा की गई पेंशन राशि नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।

पीएफआरडीए अटल पेंशन योजना के तहत कुल नामांकन को और आगे बढ़ाने तथा भारत को एक पेंशनभोगी समाज बनाने की दिशा में योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सफलता की कहानी

कृषि योग्य भूमि के विकास के लिए विभिन्न उपदान प्रदान करने पर पूरन चन्द ने राज्य सरकार का आभार जताया

*** उद्यान विभाग द्वारा निचले क्षेत्रों के लिए विकसित सेब की किस्में पूरन चन्द के लिए बनी वरदान**

मेहनत का फल सदैव सुखदायी होता है। कांगड़ा जिले की शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दुर्गेला के पूरन चंद ने अपने समर्पण, कड़ी मेहनत और लीक से हटकर सोच से इस कहावत को चरितार्थ किया है। प्रदेश के छोटे से किसान पूरन चन्द कुछ साल पहले तक अपनी जमीन पर गेहूं और अन्य पारंपरिक फसलों की खेती कर रहे थे। उनकी लीक से हटकर सोच तथा कुछ अलग करने की भावना और राज्य बागवानी विभाग के अधिकारियों से मिली प्रेरणा से उन्होंने अपनी लगभग दो बीघा भूमि में डोरसेट गोल्डन और अन्ना किस्म के सेब के पौधे लगाये।

बागवानी क्षेत्र में पूरन चंद की विकास यात्रा लगभग तीन साल पहले 2018 में शुरू हुई थी। पूरन चन्द राज्य सरकार की पानी के टैंक के निर्माण और कृषि भूमि के विकास के लिये कार्यान्वित की जा रही योजना से प्रेरित हुए थे। वह राज्य के शिमला जिले के सेब उत्पादक क्षेत्रों के लोगों की मजबूत आर्थिकी से हमेशा प्रभावित थे। प्रदेश सरकार के बागवानी विभाग द्वारा राज्य के निचले क्षेत्रों के लिये उपयुक्त सेब की किस्मों को विकसित करने के लिए तैयार योजना का लाभ उठाते हुए पूरन चंद ने अपनी जमीन पर एक सेब का बागीचा लगाने का फैसला किया।

पूरन चंद का कहना है कि जब उन्होंने अपने खेत में सेब की पौध लगाना शुरू किया तो उनकी धर्मपत्नी ने भी उनके इस विचार का विरोध किया क्योंकि उन्हें इस योजना की सफलता पर संशय था। उन्होंने कहा कि वह अपने निर्णय पर अडिग और अपनी जमीन पर सेब फार्म स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे।

पूरन चंद को विभाग के अधिकारियों द्वारा सभी तकनीकी जानकारी प्रदान की गई और तीन साल की अल्प अवधि के साथ उन्हें अपनी कड़ी मेहनत का फल मिलने लगा। पिछले तीन वर्षो के दौरान पूरन चंद ने 100 से 150 रुपये प्रति किलो की दर से लगभग 1.50 लाख रुपये के सेब की बिक्री की। उनका कहना है कि वह अपने बगीचे में रासायनिक खाद या स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि दालों, रसोई के कचरे, तिलहन, गोमूत्र और गोबर से बने विभिन्न प्रकार के जैविक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। पूरन चंद ने लीज पर जमीन लेकर लगभग 28 हजार सेब पौधों की नर्सरी भी तैयार की है। उनका कहना है कि इस वर्ष सर्दियों में वह स्थानीय किसानों को लगभग 3500 पौधे बेचेंगे। पूरन चंद का कहना कि स्थानीय लोग और पर्यटक सीधे उनके खेत से यह पौधे खरीद सकते हैं।

पूरन चंद ने बताया कि उनकी धर्मपत्नी गांव के स्कूल में शिक्षिका हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण करीब दो साल तक स्कूल बंद रहने पर उन्होंने सेब बागीचे को विकसित करने के लिए हर संभव सहायता की। उन्होंने न केवल सेब की नर्सरी विकसित की, साथ ही इच्छुक किसानों को सेब पौधे भी उपलब्ध करवाये। उनका कहना है कि आज वह देश भर के प्रगतिशील किसानों को सेब के पौधों की आपूर्ति कर रहे हैं। आज देश के विभिन्न भागों में उनके ग्राहक हैं और कर्नाटक, उत्तरी–पूर्व, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि के किसानों को उन्होंने सेब के पौधों की आपूर्ति सुनिश्चित की है।

पूरन चंद को राज्य सरकार की ओर से एंटी–हेल–नेट के लिए 80 प्रतिशत का अनुदान भी मिला है। वर्तमान में उन्होंने चार कनाल बागीचे में अन्ना और डोरसेट सेब की किस्मों के लगभग 150 पौधे लगाये हैं। उन्होंने अपने खेतों में लगभग 100 से अधिक सेब के पौधे लगाने की भी योजना तैयार की है। स्वरोजगार की राह पर चलने का आहवान करते हुए उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि वह नौकरी के पीछे भागने के बजाये सेब, कीवी और अमरूद के पौधे लगाकर बागवानी को अपनायें।

पूरन चंद से प्रेरित होकर शाहपुर क्षेत्र के दुर्गेला, भनाला, बांदी, राजोल, धडंबा गांवों के अधिकतर किसानों ने सेब के पौधे लगाये हैं, जिससे उनकी आर्थिकी को संबल मिला है, क्योंकि ये पौधे दो से तीन वर्षो में फल देना शुरू कर देते हैं। आज पूरन चन्द क्षेत्र में सेब की खेती अपनाने के इच्छुक किसानों को हर संभव जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं।

पुलिस विभाग में सुरक्षा उपकरणों की खरीद पर 2.37 करोड़ व्ययःजय राम ठाकुर

मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के 29 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ओक ओवर से राज्य पुलिस विभाग के 29 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने पुलिस विभाग के 40 लेजर स्पीड मीटर कैमरा, 124 बॉडी वॉर्न कैमरा व 129 लाइट बैटन भी लॉन्च किये।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लेजर स्पीड मीटर कैमरा, बॉडी वॉर्न कैमरा और लाइट बैटन सड़क सुरक्षा उपकरणों की खरीद पर 2.37 करोड़ रुपये और वाहनों की खरीद पर 2.52 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। राज्य सरकार प्रदेश में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके दृष्टिगत पुलिस विभाग को विश्व स्तरीय तकनीक से युक्त आधुनिक उपकरण और सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने विभाग के कार्यो की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल पुलिस के जवानों ने अपनी प्रतिभा और दक्षता से देश भर में अलग पहचान बनाई है।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि लेजर स्पीड मीटर कैमरा के माध्यम से यातायात प्रबंधन को और बेहतर बनाने तथा दुर्घटनाओं में कमी लाने में मदद मिलेगी। बॉडी वॉर्न कैमरा के माध्यम से यातायात व्यवस्था में तैनात जवानों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता व दक्षता लाने में सहायता मिलेगी। लाइट बैटन के माध्यम से रात के समय जवानों द्वारा किये गये इशारों को समझने में चालकों को सहायता मिलेगी।

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व के तहत पुलिस विभाग को 9.50 लाख रुपये की लागत से 300 पार्का जैकेट व 500 रिफ्लेक्टिव ट्रैफिक वैस्ट भी उपलब्ध करवायी गयी हैं।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एन. वेणु गोपाल और अभिषेक त्रिवेदी भी उपस्थित थे।

फ्री मेडिकल कैंप में सब लोग स्वास्थ्य जांच करवा कर लाभ उठायें:धूमल

शिमला/शैल। हमीरपुर जिला की बड़सर विधानसभा के बिझड़ी कस्बे में पंडित दीनदयाल अंत्योदय सेवा समिति द्वारा लोगों की मुफ्त में जांच करने के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल मेडिकल कैंप के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे।

पूर्व मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल अंत्योदय सेवा समिति ने करोना काल में लोगों की बहुत सेवा की है जिसके लिए समिति की सारी टीम बधाई की पात्र है। जिसके लिये इनको बधाई देता हूं। इस मेडिकल कैंप में हर तरह के रोग विशेषज्ञ चिकित्सक यहां आयेंगे। आजकल फसल का काम भी है लेकिन यह जो मौका आपको घर द्वार पर मिल रहा है इसको यूं ही ना जाने दें बल्कि इसका लाभ उठायें। भिन्न-भिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक यहां आये हुए हैं तो आप संबंधित बीमारी के लिये स्वास्थ्य जांच जरूर करवायें।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सांसद अनुराग ठाकुर ने सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के तहत आने को मोबाइल एंबुलेंस वैन लोगों के घर द्वार पर इलाज के लिए उपलब्ध करवाई है जिनमें

है। पंडित दीनदयाल का भी यही लक्ष्य था अंत्योदय यानी कि गरीबों में भी जो सबसे ज्यादा गरीब हो उसका उत्थान करना। उसके बाद अन्य जरूरतमंद की मदद करना। उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही समिति के सभी सदस्य काम कर रहे हैं और आपका सहयोग करने के लिए चंडीगढ़ से ऊना से हमीरपुर से और अन्य स्थानों से जो डॉक्टर यहां फ्री मेडिकल कैंप में लोगों के इलाज करने पहुंचे हैं उन सब का स्वागत भी करता हूँ और उन्हें बधाई भी देता हूँ। हम लोग तो साधन मात्र हैं लेकिन इस धरती पर डॉक्टर भगवान का स्वरूप होते हैं भगवान जीवन देता है तो डॉक्टर उस जीवन को बचाने का काम करता है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आजकल जो हमारा खान-पान की चीजें जुटाने का तरीका हो गया है वह काफी चिंताजनक है, जल्दी फसल तैयार हो फ़ल तैयार हो सब्जी तैयार हो उसके लिए जो रसायनिक दवाइयां हम उपयोग में लाते हैं। कैसी-कैसी खाद डालते हैं उनका असर 40 दिनों तक रहता है। और जब वही अनाज फल सब्जी हम खाते हैं तो उसका असर हमारे ऊपर भी होता है। फिर कई बार बीमार हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि कैसे बीमार हो गये। तब स्वास्थ्य निरीक्षण जरूरी हो जाता है और हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य जांच के लिए महंगे महंगे संस्थानों में नहीं जा सकते। ज्यादा पैसे नहीं खर्च सकते। आपको डॉक्टर के पास में ना जाना पड़े बल्कि डॉक्टर आपके घर द्वार पर आये इसीलिये दीनदयाल अंत्योदय समिति ने बिझड़ी के मैदान में यह स्वास्थ्य सेवा आज लोगों को उपलब्ध करवाई अनेकों रोगों के साथ-साथ कैंसर की भी जांच होती है। ऐसी ही एक एंबुलेंस गाड़ी जो मुंबई से आयी थी और जिसकी कीमत ढाई करोड़ रुपये थी उससे जांच का लाभ कई महिलाओं ने उठाया है। कैंसर बीमारी का यदि शुरुआती स्टेज में पता लग जाये तो उसका इलाज संभव हो जाता है तो ऐसी महिलाओं जिनको शुरुआती समय में बीमारी का पता चला अभी इलाज करवा कर स्वस्थ हो चुकी हैं। इसलिये आप सबसे निवेदन करता हूँ कि यदि समय रहते बीमारी का पता चल जाये तो डॉक्टर भी आसानी से इलाज करके हमें स्वस्थ बना सकते हैं। तो जब इस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं हमें घर द्वार पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं तो हमें भी इन सेवाओं का लाभ लेने से पीछे नहीं रहना चाहिए। इस अवसर पर मौजूद पदमश्री अवार्ड से सम्मानित करतार सिंह सौंखला का स्वागत अभिनंदन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह और डॉ डी एस राणा पद्मश्री अवार्डी दोनों ही हमारे जिले और हमारे प्रदेश की शान हैं। करतार सिंह बहुत योग्य व्यक्ति हैं और इनकी कला के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कायल हो चुके हैं। बांस की कलाकृतियों को बनाने का प्रशिक्षण आजकल यह दे रहे हैं तो यहां पर भी इच्छुक महिलायें इस कला को सीखकर हुनरमंद बन सकती हैं। इस अवसर पर पूर्व विधायक एवं भाजपा जिलाध्यक्ष बलदेव शर्मा तथा श्रम एवं भवन निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन राकेश बबली सहित पंडित दीनदयाल अंत्योदय समिति की सभी सदस्य एवं के विशेषज्ञ चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ और आसपास के क्षेत्रों के लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय जन सम्पर्क दिवस पर "नई दुनिया बनायें: विश्वास बढ़ायें " विषय पर सम्मेलन का आयोजन

शिमला/शैल। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया (पी.आर.एस.आई) के शिमला चैप्टर और सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय जन सम्पर्क दिवस के अवसर पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का विषय जन सम्पर्क द्वारा नई दुनिया बनायें : विश्वास बढ़ायें, था।

सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुये निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क हरबंस सिंह ब्रसकोन ने कहा कि विश्वास मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें संवाद और संचार निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि जन सम्पर्क व्यवसायियों को लोगों का विश्वास जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिये तथा मीडिया के विभिन्न साधनों का उपयोग करके वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिये।

उन्होंने कहा कि जन सम्पर्क व्यवसायियों को सरकार की कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिये योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिये ताकि अधिक से अधिक लोग इनसे लाभान्वित हो सकें। उन्हें विश्वसनीय दृष्टिकोण, अच्छे आदर्शो और सभ्य आचरण के साथ काम करना चाहिए ताकि जनता उन पर भरोसा कर सके।

हरबंस सिंह ब्रसकोन ने कहा कि पारम्परिक मीडिया के अलावा वर्तमान में तकनीकी प्रगति के साथ आज हमारे पास सोशल मीडिया की ताकत है, जो प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम बन कर उभरा है। उन्होंने कहा कि पीआर पेशेवरों को सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को जमीनी स्तर तक प्रचारित करने के लिए नवीनतम उपकरणों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना चाहिये।

उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि हिमाचल प्रदेश देश के अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बन कर उभरा है और हिमाचल विभिन्न मानकों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है। यह सरकार के निरन्तर प्रयासों और राज्य के लोगों के सक्रिय सहयोग के कारण संभव हुआ है।

हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के सदस्य प्रो. शशिकांत ने अपने सम्बोधन में इस बात पर विशेष बल दिया कि जन सम्पर्क और मीडिया व्यवसायियों को बिना किसी भय या दबाव के सच्चाई को सामने लाने के उद्देश्य से काम करना चाहिये। उन्होंने कहा कि यह सबसे महत्वपूर्ण है कि समाज को समृद्धि और विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए विश्वसनीय तरीके से कार्य किया जाये।

प्रो. शशिकांत ने कोरोना महामारी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाये गये विश्वास के कारण ही देश की जनता ने महामारी के विरूद्ध सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि भारत ने न केवल विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया, बल्कि अन्य देशों को भी वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि इसी तरह उनके द्वारा अर्जित विश्वास के कारण ही देश की जनता भारत सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों से आश्वस्त है और आज हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं।

उन्होंने जन सम्पर्क और मीडिया व्यवसायियों से पूरे समाज को लाभान्वित करने के लिए सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों के बारे में जन जागरूकता पैदा करने का आग्रह किया।

उन्होंने जन सम्पर्क एवं मीडिया व्यवसायियों से सरकार की नीतियों एवं योजनाओं के प्रचार के अतिरिक्त विभिन्न बड़े सामाजिक मुद्दों पर जन जागरूकता लाने का आग्रह किया।

इससे पूर्व, पीआरएसआई शिमला चैप्टर के अध्यक्ष प्रदीप कंवर ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि जन सम्पर्क तथा संचार व्यवसायियों द्वारा प्रतिवर्ष पब्लिक रिलेशंज सोसायटी ऑफ इण्डिया के नेतृत्व में 21 अप्रैल को देशभर में राष्ट्रीय जन सम्पर्क दिवस अपने को जन सर्म्पक व्यवसायी के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है।

उन्होंने कहा कि जन सम्पर्क अपने विचार व्यक्त करने तथा संचार के विभिन्न माध्यमों के उपयोग से लोगों के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जन सम्पर्क की भूमिका और अधिक बढ़ी है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जन सम्पर्क व्यवसायी अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें।

उन्होंने राष्ट्रीय जन सम्पर्क दिवस के अवसर पर पीआरएसआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पाठक का सन्देश भी पढ़ा।

इस सम्मेलन में आयोजित विचार विमर्श कार्यक्रम में पीआरएसआई के सदस्यों तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जन संचार के विद्यार्थियों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया।

पीआरएसआई शिमला चैप्टर के सचिव रणवीर वर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1958 में पीआरएसआई का गठन जन सम्पर्क को एक व्यवसाय के रूप में बढ़ावा देने तथा इसे सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मीडिया तथा जन सम्पर्क व्यवसायियों के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जायेंगी।

पीआरएसआई के राष्ट्रीय परिषद् के सदस्य यादविन्द्र चौहान, हिप्र विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जन संचार विषय के विभागाध्यक्ष प्रो. विकास डोगरा, प्रो. अजय कुमार, अन्य सदस्य तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इस सम्मेलन में उपस्थित थे।

मण्डी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए संयुक्त उपक्रम समझौता हस्ताक्षरित

शिमला/शैल। जिला मण्डी के नागचला में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए नई दिल्ली में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और केन्द्रीय नागरिक

विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया की उपस्थिति में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई) तथा प्रदेश सरकार के मध्य संयुक्त उपक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए गये। इस समझौते से मण्डी में अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का मार्ग प्रशस्त होगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हवाई अड्डे से न केवल प्रदेश में हवाई यातायात की सुविधा सुदृढ़ होगी, बल्कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यह हवाई अड्डा वाईड बॉडिड विमानों के उतरने के लिए उपयुक्त होगा जिसमें अन्तरराष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल हैं।

मण्डी जिला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे में 3150 मीटर का रन-वे विकसित किया जायेगा तथा इसके लिए 2840 बीघा भूमि चिन्हित की गई है। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने इसके लिए ऑबस्टेकल लिमिटेशन सरफेस (ओ.एल.एस.) तथा लीडार (लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग) सर्वेक्षण भी करवाये हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि ओएलएस और लीडार सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मण्डी में हवाई अड्डा रात में लैंडिंग और वर्षभर संचालन के साथ-साथ एबी-320 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए व्यवहार्य और उपयुक्त है।

मुख्यमंत्री ने एटीआर 42-600 को शिमला हवाई अड्डे पर उतारने और उड़ान-2 के तहत शिमला-कुल्लू -धर्मशाला के लिए उड़ान संचालन को प्राथमिकता क्षेत्र रूट बनाने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने उड़ान-2 के अन्तर्गत चंडीगढ़-धर्मशाला रूट को चम्बा तक और शिमला-रामपुर रूट का विस्तार किन्नौर तक करने का आग्रह किया।

केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने इस अवसर पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। ए.ए.आई. के अध्यक्ष, संजीव कुमार, सचिव, नागरिक उड्डयन, राजीव बंसल, प्रधान सचिव पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन देवेश कुमार, एएआई और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने ललित कला महाविद्यालय के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश में ललित कलाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि युवाओं को इस दिशा में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

राज्यपाल जवाहर लाल नेहरू

राजकीय ललित कला महाविद्यालय चौड़ा मैदान के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे।

राज्यपाल ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर सन्तोष व्यक्त करते हुए कहा कि ललित कला महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में सदियों से विभिन्न प्रकार की शिक्षा पद्धतियों का विकास हुआ है, लेकिन ललित कलाओं विशेषकर संगीत में हमने दुनिया को एक संदेश दिया है।

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा, माता सरस्वती को संगीत की देवी कहा जाता है और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहां संगीत समारोह का आयोजन नहीं किया जाता है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शास्त्रीय संगीत और कला के क्षेत्र में विशेष कार्य किए जा रहे हैं, जिन्हें विस्तार प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि युवा कलाकारों को अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने की जरूरत है। उन्होंने महाविद्यालय के पुस्तकालय के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने महाविद्यालय पत्रिका कला दर्शन के पहले संस्करण का विमोचन भी किया।

जवाहर लाल नेहरू राजकीय ललित कला महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉ. मीना शर्मा ने राज्यपाल का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा महाविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने पिछले दो वर्षो के दौरान महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों और उपलब्धियों का भी विवरण दिया। उन्होंने कहा कि ललित कला के विभिन्न विषयों में 157 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें 93 छात्र और 64 छात्रायें हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही महाविद्यालय का नया परिसर बन कर तैयार होगा।

इस मौके पर छात्राओं ने शास्त्रीय और वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति भी दी।

निदेशक, उच्चतर शिक्षा डॉ. अमरजीत शर्मा, राजकीय महाविद्यालय कोटशेरा की प्रधानाचार्य डॉ. अनुपमा गर्ग, अभिभावक शिक्षक संघ की अध्यक्ष रितु शर्मा, विभिन्न महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यो के अतिरिक्त अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

केन्द्रीय मंत्री से ऊना में विद्युत वाहन विनिर्माण पार्क के लिए सहयोग प्रदान करने का आग्रह:मुख्यमन्त्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भेंट की।

मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीद केन्द्र

खोलने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन 11 खरीद केन्द्रों के माध्यम से गेहूं की खरीद की जायेगी।

उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से ऊना में विद्युत वाहन विनिर्माण पार्क के लिए सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया और कहा कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के साथ-साथ औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने उन्हें अवगत करवाया कि राज्य सरकार ने कुल्लू के लिए स्वीकृत बुनकर केंद्र को कार्यशील बनाने के लिए तेजी से कार्य किया है। उन्होंने इसके लिए विशेषज्ञ सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया।

उन्होंने अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे में बद्दी नोड स्थापित करने का आग्रह करते हुए कहा कि इसके लिये मंत्रालय की सहायता महत्त्वपूर्ण होगी।

केन्द्रीय मंत्री ने मंत्रालय के अधिकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करने और इस मामले में तीव्र कार्यवाही करने को कहा।

मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने चर्चा के दौरान बहुमूल्य सुझाव दिये।

ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, भाजपा के राज्य अध्यक्ष सुरेश कश्यप, विधायक रीना कश्यप और हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर इस अवसर पर उपस्थित थे।

आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत हासिल करेगी:प्रतिभा सिंह

शिमला/शैल। सासंद प्रतिभा सिंह ने दावा किया है कि प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बनायेगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने पूर्व में किये गए विकास कार्यो के आधार पर लोगों के बीच जाकर वोट मांगेगी।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाजपा जो कभी महंगाई के नाम पर बड़े बड़े ढोल पिटती थी, आज खामोश बैठी है। आज गैस सिलेंडर एक हजार से ऊपर चला गया है। तत्कालीन यूपीए सरकार के समय जब यही गैस सिलेंडर 400 रुपए के आस पास मिलता था, उस समय यही भाजपा के नेता कहते फिरते थे कि उनके सत्ता में आने के बाद इसके आधे मूल्य किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि उस समय चुनावों के दौरान नरेंद्र मोदी ने देश मे हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था, जो आज दिन तक इस दूसरे कार्यकाल में भी पूरा नही हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश मे बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी पर कोई बात नही करती।

प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में हुए उप चुनावों में कांग्रेस की जीत का मुख्य कारण प्रदेश में स्व. वीरभद्र सिंह के विकास कार्यो का ही रहा। उन्होंने कहा कि आज भी जितने भी प्रदेश में विकास कार्यो के वर्तमान सरकार द्वारा फीते काटे जा रहें है वह सब पूर्व कांग्रेस सरकार के समय पूरे बजट के साथ शुरू किए गए थे। उन्होंने कहा कि आज सरकार के पास अपना खर्च चलाने तक को पैसा नही है।

प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की ऐसी कोई उपलब्धि नही है जिसके लिए वह लोगों के बीच जाकर अपने लिये वोट मांग सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ नगर निगम चुनावों के बाद विधानसभा चुनावों में भी अपनी शानदार जीत हासिल करेगी।

आधुनिकीकरण की दिशा में काम करें अधिकारी:डॉ. रजनीश

शिमला/शैल। प्रधान सचिव वन डॉ. रजनीश ने वन विभाग के मुख्यालय में बैठक की अध्यक्षता की

डॉ. रजनीश प्रधान सचिव वन ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यालय का दौरा किया और बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मुख्यालय में तैनात वन अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वन विभाग सबसे पुराने विभागों में से एक है तथा वन विभाग के अधिकारियों को आधुनिकीकरण की दिशा में काम करना चाहिए। उनके अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी के साथ-साथ आधुनिक उपकरणों का उपयोग विभाग द्वारा विशेष रूप से कार्यो में आसानी लाने के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बदलाव आवश्यक है और हमें समुदायों की सेवा के लिए इन आधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए। प्रमुख सचिव वन का कार्यभार संभालने के पश्चात् उनका वन विभाग के मुख्यालय में पहला दौरा था।

अजय कुमार प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन बल प्रमुख और राजीव कुमार प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी ने वन विभाग के कार्यो पर प्रस्तुति दी। राज्य में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में आर के गुप्ता ए पी सी सी एफ (एफ सी ए), अनिल ठाकुर ए पी सी सी एफ (वाइल्ड लाइफ), ओ पी सोलंकी ए पी सी सी एफ (एडमिन), नागेश गुलेरिया, ए पी सी सी एफ एवं सी पी डी जाइका परियोजना, एस के कप्टा सी सी एफ (मैनेजमेंट), एस डी शर्मा सी सी एफ शिमला सहित मुख्यालय में तैनात अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

नड्डा की असफल जनसभाएं और निगम चुनावों का टलना सरकार के लिये खतरे के संकेत

क्या जयराम सरकार की हालत 2014 में दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार जैसी होती जा रही है

शिमला/शैल। आप ने जब से हिमाचल में विधानसभा चुनाव लड़ने का एलान किया है उसके बाद जयराम सरकार और भाजपा ने जो भी परोक्ष/ अपरोक्ष प्रतिक्रियाएं दी हैं तथा राजनीतिक कदम उठायें हैं उन्हें आप की घोषणा के परिदृश्य में देखना समझना अवश्य हो जाता है। क्योंकि आप पंजाब की जीत के बाद दिल्ली से हिमाचल तक के पूरे क्षेत्र में भाजपा के लिये एक सीधी चुनौती बन चुका है। इस चुनौती को सार्वजनिक मंचों से नकारना भाजपा और उसके भक्तों की राजनीतिक आवश्यकता और विवशता बन चुका है। लेकिन इस नकार से स्थितियां नहीं बदल जाती हैं और किसी भी विश्लेषन और आकलन के लिये इन्हें संज्ञान में रखना इमानदारी की मांग हो जाता है। इस परिपेक्ष में यदि राष्ट्रीय स्तर पर नजर डाले तो पांच राज्यों में हुये चुनावों में चार में जीत दर्ज करने के बाद हुये चार राज्यों के उपचुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। क्योंकि जीत का उपहार लोगों को महंगाई के रूप में मिला। यह महंगाई हिमाचल और गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी सिर चढ़कर बोलेगी यह तय है।

हिमाचल में जब चारों उपचुनाव में भाजपा को हार मिली थी तब प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चायें उठी थी। इन चर्चाओं को भाजपा की विस्तारित कार्यकारिणी में उठे सवालों से भी अधिमान मिला था। लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हिमाचल से ताल्लुक रखना नेतृत्व परिवर्तन के सवालों पर भारी पड़ा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नडडा का प्रदेश के नेतृत्व को कितना और कैसा संरक्षण हासिल है इसका खुलासा उस ब्यान से बाहर आ गया है जब नड्डा ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि वह दिल्ली में जयराम ठाकुर के वकील हैं। बल्कि नड्डा वहीं नहीं रुके और धूमल को लेकर भी यह कह दिया कि पाटी गुण दोष के आधार पर फैसले लेती है। नड्डा के इस ब्यान से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिमाचल में पार्टी को सत्ता में वापसी लाने की जिम्मेदारी सीधे नड्डा और जयराम के कंधो पर आ गयी है। इस जिम्मेदारी में धूमल और शान्ता की क्या और कितनी भूमिका रह गयी है इसका अंदाजा भी नड्डा की कांगड़ा रैली के लिए छपे पोस्टरों में शान्ता-धूमल के चित्रों के गायब रहने से लग जाता है। इस परिदृश्य में जयराम सरकार के अब तक के कार्यकाल का आकलन और उसमें नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाम पर देश को उनके योगदान की भूमिका की चर्चा किया जाना आवश्यक हो जाता है। स्मरणीय है कि केंद्र द्वारा हिमाचल से 69 राष्ट्रीय राजमार्गो का तोहफा दिये जाने की पहली सूचना नड्डा के पत्र से प्रदेश की जनता को मिली थी। इन राष्ट्रीय राजमार्गो की व्यवहारिक स्थिति क्या है यह पूरा प्रदेश जानता है। नड्डा प्रदेश में दो बार मंत्री रहे चुके हैं। स्वस्थ और वन जैसे विभागों का प्रभार उनके पास रहा है। उन्हीं के काल में स्वस्थ विभाग में घोटाला हुआ था और निदेशक की गिरफ्तारी तक हुई थी। बतौर मंत्री नड्डा कितने सफल तथा विश्वसनीय रहे हैं यह प्रदेश की जनता अच्छे से जानती है। ऐसे में आज जब सरकार को रिपीट करवाने की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली है तो यह स्वभाविक है कि जय राम सरकार की कारगुजारीयों के साथ ही उनके अपने समय में घट चुके महत्वपूर्ण घटनाक्रम तुरंत से जनता के जहन और जुबान पर आ जायेंगे। आज यह सर्वविदित है कि नड्डा की पीटरहॉफ में हुई सभा में भी कुर्सियां खाली रही हैं। कांगड़ा की रैली में भी यही परिदृश्य रहा है। लोग सभा से उठकर चले गये। जय राम ठाकुर ने मुफ्ती की घोषणा केजरीवाल के एलान के बाद की है। इस परिदृश्य में यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की स्थिति दिल्ली शीला दिक्षित की सरकार जैसी बनती जा रही है।

यही नहीं शिमला नगर निगम के चुनाव जिस तरह से अनिश्चितता में चले गये हैं उसका संदेश भी सरकार की सेहत के लिये नुकसान देह होने जा रहे है। क्योंकि इन चुनाव से पहले लायी गयी शिमला डवैलप्मैंट प्लान पर जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं उभरी है उससे सरकार की नियत और नीति दोनों सन्देह के घेरे में आ खड़ी हुई है। सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर प्रदेश उच्च न्यायालय में गंभीर सवाल उठे हैं। मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त के मामलों पर भी मुख्यमंत्री आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति में पहुंच गये हैं। जैसे-जैसे चुनाव निकट आते जायेंगे उसी अनुपात में सरकार सवालों के घेरे में फसती चली जायेगी। क्योंकि आज तक जयराम सरकार एक ही सिद्धांत पर चली है कि न तो अदालती फैसलों को अधिमान दोऔर न ही कठिन सवालों वाले पत्रों का जवाब दो। लेकिन चुनावी वक्त में यही नीति गले की फांस बन जाती है।

अध्यक्ष को लेकर प्रदेश कांग्रेस संकट में क्यों

शिमला/शैल। प्रदेश विधानसभा के चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं इसकी संभावनायें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस बार आम आदमी पार्टी की दस्तक के बाद यह मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना प्रबल हो गयी हैं। 2014 से लेकर 2019 लोकसभा चुनावों तक हुये चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद 2021 में हुये चारों उपचुनाव कांग्रेस ने इस हार को रोकने का जो सफल प्रयास किया था उसकी धार को पांच राज्यों में मिली हार ने इस कदर कुन्द कर दिया है कि कांग्रेस को इस हार की मानसिकता से बहार निकलने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर पेशेवर चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सेवा लेने के मुकाम पर पहुंचा दिया है। इस सबका प्रभाव प्रदेश की राजनीति पर यह पढ़ा कि भाजपा ने कांग्रेस के स्थान पर आप को अपना पहला प्रतिद्वन्द्धी घोषित कर दिया है। कांग्रेस को चुनावी राजनीति से बाहर कर दिया है।

इस वस्तुस्थिति से भाजपा और आप को क्या लाभ मिलेगा इस सवाल से ज्यादा बड़ा प्रसन्न यह खड़ा हो गया है कि इससे कांग्रेस को कितना नुकसान होगा। इस समय तक आप के आने से कांग्रेस को ही ज्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि उसी के ज्यादा लोग कांग्रेस छोड आप में गये हैं। ऐसे में यह स्पष्ट होता जा रहा है कि कांग्रेस को आप और भाजपा दोनों से एक साथ राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जबकि भाजपा कांग्रेस को इस लड़ाई से ही बाहर होना करार देकर सारे नुकसान का रुख कांग्रेस की और मोड दिया है। जनता में भी यह चर्चा चल पड़ी है कि कांग्रेस तो सारे परिदृश्य से पहले ही बाहर हो गयी है। व्यवहारिक तौर पर भी कांग्रेस की एकजुटता और भाजपा-आप के प्रति आक्रमकता सारे परिदृश्य से ही गायब हो गयी है। जबकि इतना कुछ भाजपा के खिलाफ उपलब्ध है कि उसका उपयोग करके कांग्रेस बनाम आप के हालात खड़े किये जा सकते थे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है और विश्लेषकों के लिये यह एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है कि कांग्रेस ऐसी तन्द्रा मे चली क्यों गयी? क्या कुछ लोग कांग्रेस को भीतर से कमजोर करने की सुपारी लेकर बैठे हैं।

कांग्रेस में जब तक स्व.वीरभद्र सिंह जिन्दा थे तब तक वह निर्विवादित रुप से मुख्यमन्त्री का चेहरा बने रहे हैं। 1993 में जब पंडित सुखराम ने इस एकछत्रता को चुनौती दी थी तो उस वक्त कैसे विधानसभा का घेराव करवाकर सुखराम के हाथ से बाजी छीन ली थी उस समय के प्रत्यक्षदर्शी यह सब जानते हैं। लेकिन आज कोई वीरभद्र सिंह कांग्रेस के पास है नहीं। आज के कांग्रेस नेता यह भी भूल गये हैं कि भाजपा-मोदी ने 2014 और 2019 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनावों में वीरभद्र के खिलाफ बने मामलों को खूब भुनाया था। यही मामले थे जिनके कारण वीरभद्र भाजपा के खिलाफ चाहकर भी आक्रमक नहीं हो पाये थे।

आज वीरभद्र की कमी को पूरा करने वाला एक भी नेता सामने नहीं है। जयराम के कार्यकाल में किस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग करके प्रदेश को कर्ज के गर्त में धकेला गया है इसके दर्जनों मामले तो कैग रिपोर्टो में दर्ज हैं। लेकिन एक भी कांग्रेस नेता इनको पढ़ने और इन पर सवाल उठाने के लिये तैयार नहीं है। यहां तब की जयराम सरकार के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करने के लिए कमेटी की घोषणा करके भी जब यह आरोप पत्र न आये तो आम आदमी को मानना पड़ेगा कि कुछ तत्व पार्टी के भीतर बैठकर संगठन को जनता की नजर में अक्षम प्रमाणित करने के प्रयासों में लगे हैं। यह इन्ही प्रयासों का परिणाम है कि हर सप्ताह अध्यक्ष का बदलाव चर्चित होता है और अंत में आकर अफवाह बनकर रह जाता है। जबकि इन मुद्दों पर हाईकमान को हरदम सूचित रखना प्रभारीयों का काम होता है। जब प्रभारी भी यह जिम्मेदारी निभाने में सफल न हो पा रहे हों तो फिर संगठन का क्या होगा यह अनुमान लगाना कठिन नहीं होगा।